भारत सरकार
भारी उद्योग और लोक उद्यम मंत्रालय
भारी उद्योग विभाग

राज्य सभा
अतारांकित प्रश्न सं. 2661
जिसका उत्तर बुधवार, 10 अगस्त, 2016 को दिया जाना है

एचएमटी घड़ी कारखाने का बंद होना

2661. श्री महेन्द्र सिंह माहरा:

क्या भारी उद्योग और लोक उद्यम मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार ने उत्तराखंड के जिला नैनीताल के रानीबाग में स्थित एचएमटी घड़ी कारखाने को पूर्ण रूप से बन्द करने का निर्णय ले लिया है;

(ख) यदि हां, तो क्या सरकार इस भूमि पर सरकारी क्षेत्र के उपक्रम की प्रदूषण रहित इकाई स्थापित करेगी या इस भूमि को किसी निजी व्यक्ति/कम्पनी को देगी; और

(ग) यदि नहीं, तो इस भूमि का उपयोग किस हेतु किया जायेगा, तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

उत्तर
भारी उद्योग और लोक उद्यम राज्य मंत्री
(श्री बाबुल सुप्रियो)

(क): जी, हां। आर्थिक कार्य संबंधी मंत्रिमंडल समिति (सीसीईए) ने दिनांक 06.01.2016 को हुई अपनी बैठक में एचएमटी वाचिज लिमिटेड, जिसमें उत्तराखंड स्थित रानीबाग इकाई शामिल है, सहित एचएमटी लिमिटेड की तीन सहायक कंपनियों को बंद करने का अनुमोदन दे दिया है।

(ख) और (ग): जी, नहीं। सीसीईए के निर्णय के अनुसार, सरकार कंपनी की अचल आस्तियों अर्थात् फ्री-होल्ड भूमि और/अथवा भवन को प्रचलित सर्किल दर अथवा बाजार दर, जो भी ज्यादा हो, पर केन्द्र सरकार के मंत्रालयों/विभागों/केन्द्र सरकार के अधीन स्वायत्त निकायों/केन्द्रीय सार्वजनिक क्षेत्र के उद्यमों/ जहां कहीं आवश्यक हो, राज्य सरकार के साथ परामर्श से पीएसबी को अंतरित करने का अधिकार ग्रहण करेगी। यदि ऊपर बताया गया केन्द्र सरकार का कोई भी संस्थान अपनी इच्छा व्यक्त नहीं करता है, तो भूमि राज्य सरकार अथवा राज्य सरकार द्वारा नियंत्रित अन्य किसी संस्थान को बेच दी जाएगी/अंतरित कर दी जाएगी। पट्टे पर धारित भूमि का अंतरण पट्टाविलेख के अनुसार किया जाएगा। तथापि, केन्द्र सरकार द्वारा अचल आस्तियों को अधिग्रहित कर लेने तक ये आस्तियां एचएमटी लिमिटेड, धारक कंपनी के संरक्षण में रहेगी।

******